शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक-23 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 27-03 जून 2024 मूल्य पांच रूपये

निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र हुये स्वीकार

- अध्यक्ष के फैसले से मुख्यमंत्री के आरोप आये सवालों में
- बालूगंज थाना में हुई एफआईआर पर भी पड़ेगा असर
- विधायकों के बिकने के आरोपों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर है मानहानि के मामले

शिमला/शैल। निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र मतगणना से एक दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं। स्मरणीय है कि प्रदेश विधानसभा में तीन निर्दलीय विधायक जीत कर आये थे और पहले दिन से ही सुक्खू सरकार को समर्थन दे रहे थे। लेकिन इस बीच राजनीतिक परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि राज्यसभा चुनाव में इन लोगों ने कांग्रेस के छः बागियों के साथ भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस की हार के बाद छः बागियों को दलबदल कानून के तहत कारवाई करके निष्कासित कर दिया। इस निष्कासन के बाद इन निर्लदलीयों ने भी विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही भाजपा ने इन्हें भी उनके क्षेत्र से उपचुनाव के लिए बागियों की तर्ज पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस के बागियों के निष्कासन के बाद उनके क्षेत्र तो रिक्त घोषित हो गये और उनके उपचुनाव भी हो गये। लेकिन इन निर्दलीयों के उपचुनाव बागियों के साथ ही न हो जायें इसलिये इनके त्यागपत्रों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। यह प्रश्न चिन्ह दो कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश गौड की शिकायत के आधार पर लगाया गया। यह आरोप लगा कि यह लोग भाजपा के पास बिक गये हैं और दबाव में आकर त्यागपत्र दिये हैं। इस आश्य की बालूगंज थाना में एक एफआईआर भी दर्ज हो गयी। इसमें हमीरपुर के आजाद विधायक आशीष शर्मा और गगरेट से कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा सेवानिवृत्ति मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को पार्टी बनाया गया। जांच के दौरान कई तरह के पुख्ता परिणाम इनके खिलाफ मिलने के दावे किये गये। इन्हीं दावों के बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी अध्यक्ष के पास एक याचिका दायर कर इन निर्दलीयों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कारवाई करने की गुहार लगा दी। पूरे चुनाव प्रचार में इन लोगों को बिकाऊ विधायक करार देकर इन्हें हराने की अपील की गयी। यह दावा मुख्यमंत्री ने किया कि उनके बिकने के कई सबूत सरकार को मिल गये हैं। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में एक भी सबूत जनता में नहीं रखा गया।

निर्दलीयों और कांग्रेस के बागियों के पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ में बिकने के आरोप लगाये गये। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के मामले तक दर्ज हुये हैं। अब जब विधान सभा अध्यक्ष ने इन निर्दलीयों द्वारा दिये गये त्यागपत्रों को बिना किसी दबाव और स्वेच्छा से दिये गये मानकर उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कारवाई न करके त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया गया है। अध्यक्ष के इस फैसले से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जांच में इनके बिकने या दबाव में होने के कोई प्रमाण नहीं आये हैं। अध्यक्ष के फैसले के बाद उनके खिलाफ बालूगंज थाना में दर्ज हुई एफआईआर पर इसका क्या असर पड़ता है यह देखना रोचक होगा। क्योंकि इस फैसले के बाद कोई भी इन्हें बिकाऊ होने का संबोधन नहीं दे पायेगा। इसी के साथ इस फैसले से मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर हुए मानहानि के मामलों पर क्या प्रभाव पड़ता है यह देखना भी रोचक होगा। मतगणना से पहले आये इस फैसले के राजनीतिक अर्थ बहुत गंभीर हो जाते हैं क्योंकि यह फैसला मुख्यमंत्री के सारे दावों के उलट माना जा रहा है।

क्या कांग्रेस से निकलते ही बागी अपराधी हो गये हैं

- चुनाव प्रचार के दौरान देन्वेद्र भुट्टो के खिलाफ दर्ज हुये आपराधिक मामलों के राजनीतिक परिणाम घातक होंगे
- सुधीर शर्मा के आरोपों पर मुख्यमंत्री कब तक खामोश रह पायेंगे
- आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के मामले कितने आगे बढ़ेंगे इस पर रहेगी नजरें

शिमला/शैल। प्रदेश में हुये लोकसभा और छः विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान कुटलैहड से भाजपा प्रत्याशी बने देवेंद्र भूट्टो और उनके बेटे करण के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हुये हैं। पहला मामला जब देहरा में दर्ज हुआ था तब उस समय देवेन्द्र भूट्टों ने यह जवाब दिया था कि वह प्रदेश उच्च न्यायालय से इस मामले में पहले ही जीत चुके हैं और उसका रिकॉर्ड पुलिस में पेश कर दिया जायेगा। इसके बाद भी इनके खिलाफ तीन और अलग-अलग मामले दर्ज हुये हैं। स्मरणीय है कि इस चुनाव प्रचार में जब मुख्यमंत्री कुटलैहड गये थे तब उन्होंने जनता से कहा था की भुट्टों को कुट्टो। मुख्यमंत्री के इस ब्यान का भाजपा ने कड़ा संज्ञान लेते हुये इसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। इसी के साथ और भी कानूनी कारवाई की गयी है। भुट्टो दिसम्बर 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। अब राज्यसभा चुनाव के दौरान वह कांग्रेस से बगावत करके

शेष पृष्ठ 8 पर.....

मुख्यमंत्री ने वनों को आग से बचाने के उपायों की समीक्षा बैठक की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वनों को आग से बचाने के उपायों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वनों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि लोगों के सहयोग से वनों में आग लगने की घटनाओं में धीरे-धीरे कमी आ रही है।

आग लगने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाने के साथ-साथ दीर्घकालिक उपाय करने के निर्देश दिये। उन्होंने इन प्रयासों में

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अब तक वनों में 1318 आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं से 2789 हेक्टेयर हरित क्षेत्र सहित 12718 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है जिससे 4.61 करोड़ रुपये का प्रारंभिक वित्तीय नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा कि वनों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार अग्निशमन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित एनडीआरएफ की एक समर्पित बटालियन गठित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि 374 वन बीट आग लगने की घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं तथा इन क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वनों में विशिष्ट प्रजातियों के पौधों के साथ-साथ शंकुधारी पौधों के क्षेत्रों में विविध प्रजाती के पौधे लगाने पर बल दिया ताकि इनसे वनों में नमी बनी रहे और आग की घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने वन विभाग को आग की घटनाओं के कारणों की जांच करने और आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए सरकारी एजेंसी से अध्ययन करवाने के निर्देश भी दिए।

नाचन और धर्मपुर के दिव्यांग मतदाताओं ने किया घर से शत प्रतिशत मतदान

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेशवासियों से लोकतंत्र के पर्व में बढ़कर भाग लेने का आहवान करते हुए कहा है कि सभी को बगैर किसी भय से निर्भिक होकर अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में एक एक मत का बहुत बड़ा महत्व है जब हम अपने भविष्य के लिए किसी भी राजनैतिक दल को अपना पूर्ण समर्थन देते है जो किसी भी लोकतांत्रिक देश की राजनीति की दिशा व दशा तय करते हैं।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा ही लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए देशहित व जनहित को सर्वोपरि रखा है। किसी भी राजनैतिक दल के लिये जब वह देश की बागडोर संभालता है उस के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और इस जिम्मेदारी का कांग्रेस ने सदैव ही पालन किया है। आज देश मे जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है वह बहुत ही चिंता की बात है। देश की एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार की आंच न आये इसके लिए उन्हें ऐसी सरकार को चुनना होगा जो सभी से न्याय करते हुए सभी के अधिकारों की रक्षा करें।

एचआईवी तथा एड्स को खत्म करने के लिए सभी मिलकर आगे आयें:राजीव कुमार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने आज हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान परिमहल शिमला में सोसायटी द्वारा सामुदायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए जिला स्तरीय नेटवर्क, राज्य स्तरीय नेटवर्क, पीपल लिविंग विद एचआईवी की क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं उपचार साक्षरता कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस दो दिवसीय कार्यशाला का विषय 'मेरा स्वास्थ्य - मेरी जिम्मदारी' है।

कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश में एचआईवी पॉजीटिव लोगों को राज्य स्तरीय तंत्र तथा जिला स्तरीय नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। इससे हिमाचल प्रदेश के सभी एचआईवी पॉजीटिव व्यक्ति मिलकर इस संक्रमण को रोकने के लिए कार्य कर सकेंगे और अपने अधिकारों व सुविधाओं के बारे में जागरूक बनेंगे।

राजीव कुमार ने कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागियों को शीघ्रातिशीघ्र जिला स्तरीय नेटवर्क का गठन कर पंजीकरण करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आईए हम सभी मिलकर एचआईवी तथा एड्स को खत्म करने के लिए आगे आएं, जिसके लिए एचआईवी जांच अवश्य करवाएं। एचआईवी पाजीटिव लोगों को इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगे आना होगा तभी हम मिलकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में कामयाब होंगे।

कार्यशाला के दौरान उपचार साक्षरता कार्यक्रम 'मेरा स्वास्थ्य - मेरी जिम्मेदारी' पर भी विस्तृत चर्चा कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।

इस अवसर पर नेशनल कॉलीजन आफ पीपल लिविंग विद एचआईवी इन इंडिया और वाईआरजी सेंटर फार एड्स रिसर्च एण्ड एजुकेशन से आए विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों द्वारा एचआईवी पॉजीटिव लोगों को आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त एंटी रेट्रो वायरल दवाइयों और आवश्यक जीवनशैली, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई।

संसदीय क्षेत्रों की मतदान प्रतिशतता लगभग 71 प्रतिशत

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एक जून, 2024 को हुये मतदान में संसदीय क्षेत्रों की मतदान प्रतिशतता लगभग 71 प्रतिशत रही।

उन्होंने बताया कि संसदीय क्षेत्र मण्डी में मत प्रतिशतता लगभग 73, हमीरपुर में 72, शिमला में 71 तथा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 68 प्रतिशत रही।

उन्होंने संसदीय क्षेत्रों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मण्डी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र आनी में लगभग 73 प्रतिशत, बल्ह में 75, बंजार में 70, भरमौर में 62, द्रंग में 74, जोगिन्द्रनगर में 68, करसोग में 72, किन्नौर में 70, कुल्लू में 71, लाहौल-स्पिति में 75, मनाली में 72, मण्डी में 75, नाचन में 77, रामपुर में 74, सरकाघाट में 67, सिराज में 75 तथा सुन्दरनगर में 76 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र बड़सर में लगभग 70 प्रतिशत, भोरंज में 69, बिलासपुर में 71, चिंतपूर्णी में 71, देहरा में 63, धर्मपुर में 63, गगरेट में 73, घुमारवीं में 72, हमीरपुर में 68, हरोली में 70, जसवां-परागपुर में 68, झण्डूता में 72, कुटलैहड़ में 76, नादौन में 72, श्रीनयना देवी जी में 73, सुजानपुर में 74, ऊना में 74 प्रतिशत मतदान हुआ।

शिमला संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र अर्की में लगभग 68 प्रतिशत, चौपाल में 67, दून में 74, जुब्बल-कोटखाई में 75, कसौली में 75, कसुम्पटी में 61, नाहन में 78, नालागढ़ में 71, पच्छाद में 72, पांवटा साहिब में 74, रोहडू में 74, शिलाई में 71, शिमला में 63, शिमला ग्रामीण में 65, सोलन में 69, रेणुका जी में 69, ठियोग में लगभग 66 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ।

इसी प्रकार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ में लगभग 62 प्रतिशत, भटियात में 65, चम्बा में 67, चुराह में 70, डलहौजी में 66, धर्मशाला में 70, फतेहपुर में 67, इंदौरा में 69, जयसिंहपुर में 62, जवालामुखी में 69, जवाली में 65, कांगड़ा में 70, नगरोटा में 71, नुरपूर में 67, पालमपुर में 69, शाहपुर में 68 तथा सुलह में लगभग 67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

प्रवक्ता ने छः विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उप-चुनावों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 76 प्रतिशत, लाहौल-स्पिति 75 व गगरेट में 73 प्रतिशत, सुजानपुर में 74, धर्मशाला में 70 तथा बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 69 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि प्रपत्र 12डी के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या 41924 रही, जिनमें 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 29879, दिव्यांगजन मतदाता 10634, जिन्होंने घर से मतदान किया तथा मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं पर तैनात 1411 मतदाताओं ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) पर मतदान किया।

संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों में 32194 मतदाताओं ने घर से किया मतदान

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के 'कोई मतदाता न छूटे' आदर्श वाक्य की अक्षरशः अनुपालना के लिए सभी वर्गों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने प्रपत्र 12डी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी चार संसदीय क्षेत्रों में अब तक 12डी प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त कुल 44562 आवेदनों में से 41252 डाक मतपत्र चुनाव विभाग को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि छः विधानसभा क्षेत्रों के उप-चुनावों के लिए अब तक 12डी प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त कुल 3651 आवेदनों में से 3380 डाक मतपत्र विभाग को प्राप्त हो चुके हैं।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संसदीय क्षेत्रों में अब तक 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 31122 मतदाताओं ने प्रपत्र 12डी के माध्यम से आवेदन किया था, जिनमें से 29619 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट किया है। इसी प्रकार दिव्यांगजन मतदाताओं से प्रपत्र 12डी के माध्यम से 11007 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 10526 ने डाक मतपत्र द्वारा अपना वोट डाला, जबकि मतदान दिवस के दिन 2433 अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मियों में से 1107 ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर पीवीसी में अपना वोट डाला।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छः विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 2747 मतदाताओं ने प्रपत्र 12डी के माध्यम से आवेदन किया था, जिनमें से 2575 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट किया है। इसी प्रकार दिव्यांगजन मतदाताओं से प्रपत्र 12डी के माध्यम से 820 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 772 ने डाक मतपत्र द्वारा अपना वोट डाला, जबकि मतदान दिवस के दिन 84 अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मियों में से 33 ने ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पीवीसी में अपना वोट डाला।

मतदान के दिन सवेतन अवकाश न देने वाले नियोक्ताओं पर लगाया जाएगा जुर्माना: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

शिमला/शैल। मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदान के दिन एक जून 2024 को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय जैसे बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगियों के लिए भी यह सवेतन अवकाश होगा और यह नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट 1981 की धारा 25 के तहत लागू होगा। उन्होंने कहा कि यह दिशा-निर्देश व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों पर भी लागू होंगे, जिनपर नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट लागू नहीं होता। इस संबंध में हिमाचल सरकार द्वारा एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह जानकारी आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी।

उन्होंने कहा कि श्रम आयुक्त एवं चीफ इन्सपेक्टर ऑफ फैक्टरीज हिमाचल प्रदेश ने सहायक निदेशक कारखाना, ऊना, सोलन और प्रदेश के सभी श्रम अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार कारखाना निरीक्षणालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के प्रावधान के संबंध में जानकारी दी है, जिसमें मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों उपायुक्त को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी, विशेषकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश मिले। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति, जो लोकसभा या विधानसभा के चुनावों के दौरान वोट देने का हकदार है, को मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति के वेतन में ऐसी छुट्टी के कारण कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीचः सीएम

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से एक जून को अपना मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि इस बार चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस पर्व में सभी की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव में एक-एक वोट क़ीमती है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है क्योंकि इस बार चुनाव बिकाऊ और टिकाऊ के बीच है। जिन लोगों ने वोट को धनबल से खरीदने का प्रयास किया है, यह समय उन्हें सबक़ सिखाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता के साथ हर सुख-दुख में साथ रही। आपदा में कांग्रेस सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया और आपदा प्रभावित 22 हजार परिवारों का फिर से बसाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पैन्शन प्रदान की। सवा साल के कार्यकाल में सात प्रतिशत महंगाई भत्ता और पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़ाकर 1000 रुपए की। इसके साथ-साथ पैन्शनर्स के एरियर को भी क्लीयर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ अन्य वर्गो के कल्याण के लिए भी योजनाए बनाई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की योजना शुरू की, हालांकि भाजपा ने इसमें रुकावटें पैदा की। इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने लंबित राजस्व मामलों का निपटारा प्राथमिकता पर किया और प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से इंतकाल के एक लाख से अधिक और तकसीम के लगभग आठ हजार मामलों का निपटारा कर लोगों को राहत प्रदान की गई।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाकर 300 रुपए की। इसके अतिरिक्त विधवाओं के 27 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क पढ़ाई और विधवाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता जैसे प्रावधान किए हैं। प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपना कर उनके भरण-पोषण और पढ़ाई की ज़िम्मेदारी क़ानूनी रूप से राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी बनाया है। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो को कांग्रेस सरकार 25 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार उपलब्ध करवा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सेब और आम का समर्थन मूल्य ऐतिहासिक 1.50 रुपए बढ़ाकर 12 रुपए किया। पहली बार किलो के हिसाब से सेब की ख़रीद सुनिश्चित की और इस सेब सीज़न में बिक्री यूनिवर्सल कार्टन में होगी। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार दूध को समर्थन मूल्य दिया गया और प्रदेश में गाय का दूध 45 रुपए तथा भैंस का दूध 55 रुपए के रेट पर ख़रीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएँ बनाई है। कांग्रेस सरकार का साढ़े तीन साल का कार्यकाल अभी बाक़ी है और हम अपना एक-एक दिन जनसेवा के लिए समर्पित करेंगे।

चुनाव परिणाम पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में होंगेःप्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मण्डी संसदीय क्षेत्र से निवर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे और देश मे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के चारों लोकसभा व छह विधानसभा चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा असफल हो गया है और भाजपा 200 पार भी नही कर पाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावों में भाजपा ने मुद्दों पर कोई बात नही की। बढ़ती मंहगाई व बेरोजगारी पर पूरी तरह खामोश रही।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने कहा कि 4 जून चुनाव परिणाम पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे।

प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिये जो जो हतकडे अपनाएं है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अनाप शनाप ब्यानबाजी कर लोगों में भय पैदा करने का असफल प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को धनबल से कमजोर करने की कोशिश की गई है पर जनबल ने इसे पूरी तरह नकार दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने इन चुनावों को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है और प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में ही भारी मतदान किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नही की गई होगी तो देश के साथ साथ प्रदेश के सभी चुनाव नतीजे कांग्रेस के पक्ष में अप्रत्याशित चौकाने वाले होंगे।

प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि उनकी मण्डी संसदीय सीट पर विक्रमादित्य सिंह की जीत पक्की है और वह रिकार्ड मतों से अपनी जीत का परचम लहरायेंगे। उन्होंने कहा कि मण्डी संसदीय क्षेत्र के लोगों पहले भी कांग्रेस के साथ थे और इस बार भी पूरी तरह कांग्रेस के ही साथ है। विक्रमादित्य सिंह ने मण्डी के विकास का जो विजन लोगों के समक्ष रखा है लोगों ने अपने मत के द्वारा उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया है ऐसा उन्हें पूरा विश्वास हैं।

जयराम ठाकुर क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैःविक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। मण्डी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्षेत्रवाद की राजनीति करते है। क्षेत्रवाद का नारा देकर लोगों की भावनाओं से खेलने का असफल प्रयास करते है। उन्होंने कहा है कि मण्डी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उप चुनावों में भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, और इस बार भी ऐसा ही होगा।

सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली व बालीचौकी में अपनी चुनावी सभाओं को सम्बोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व.वीरभद्र सिंह ने सराज क्षेत्र में विकास की जो नींव रखी थी वह फलीभूत हुई है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने कभी भी न तो क्षेत्रवाद की कोई राजनीति की और न ही किसी क्षेत्र से कोई भेदभाव। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने इस क्षेत्र के लिये जो भी मांगा वह वीरभद्र सिंह ने दिल खोल कर दिया।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बार मण्डी संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने एक ऐसी अभिनेत्री को अपना प्रत्याशी बनाया है जिसे न तो कोई समझ है और न ही क्षेत्र की कोई जानकारी। वह आज दिन तक अपना विजन तक नही बता पाई है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर, इधर उधर की बाते कर लोगों का मनोरंजन कर रही है। उन्होंने कहा कि एक महिला होते हुए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 4 जून को चुनाव हारने के बाद वह अपनी नगरी मुंबई लौट जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज वह अपने को मण्डी की बेटी बता कर लोगों से वोट मांग रही है। आपदा के समय इस बेटी ने इस क्षेत्र में किसी की कोई सुध तक नही ली।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 15 माह के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में 22 हजार से अधिक पद सृजित किये है। उन्होंने कहा की भाजपा प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब चुनाव के चार दिन शेष रह गए है। उन्होंने भाजपा के किसी भी प्रलोभन से बचने व क्षेत्र के विकास के लिये उन्हें वोट देने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें फैसला करना है कि उन्हें यहां से कैसा सांसद चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल कर व महिलाओं को हर महीने 1500 की सम्मान राशि देने की गारंटी को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो कर्मचारी हितेषी ही है और न ही महिला हितेषी। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने महिलाओं को दी जाने वाली 1500 रुपए की इस योजना को बंद करने के लिये चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिये 800 करोड़ का बजट रखा है और प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को यह राशि 6 जून से मिलनी शुरू हो जायेगी। कांग्रेस जो कहती है उसे हर हाल में पूरा करती है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह सांसद बनने के बाद वह मण्डी संसदीय क्षेत्र के विकास की नई गाथा को शुरू करेंगे। उन्होंने लोगों से उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि वह केंद्र में जाकर किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास की एक नई इबारत लिखेंगे।

नाचन और धर्मपुर के दिव्यांग मतदाताओं ने किया घर से शत प्रतिशत मतदान

शिमला/शैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि 12 डी फार्म भरने वाले 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं के घर से वोट डालने की प्रक्रिया के अन्तर्गत नाचन और धर्मपुर विधानसभाओं के शत प्रतिशत दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया हैं और बल्ह विधानसभा में सबसे अधिक 98.06 प्रतिशत 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं ने 27 मई तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अपूर्व देवगन ने बताया है कि घर से मतदान करने की प्रक्रिया 29 मई तक जारी रहेगी। जिला में घर-घर मतदान प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए 124 पोलिंग टीमें तैनात की गई हैं। उनके द्वारा पूरी गोपनियता के साथ मतदान करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के 12 डी फार्म स्वीकार हुए हैं और निर्धारित तिथि को घर पर उपस्थित नहीं पाए गए थे। उन घरों में पात्र मतदाताओं से मतदान करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां पुनः दस्तक दे रही हैं। उन्होंने अभी तक मतदान न कर पाने वाले मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह मतदान की अन्तिम तिथि 29 मई को घर पर ही मौजूद रहें ताकि पोलिंग टीमें उनका मतदान करवा जा सके।

उन्होंने बताया कि 27 मई तक मंडी जिला में 98.57 प्रतिशत दिव्यांग मतदाता और 96.85 प्रतिशत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में यह आंकड़ा 97.91 प्रतिशत और 96.91 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि जिला में 85 वर्ष से अधिक आयु के 9232 बुजुर्ग मतदाताओं में से 6303 मतदाताओं घर से मतदान का विकल्प चुना था और जबकि 10990 दिव्यांग मतदाताओं में से 2243 मतदाताओं घर से मतदान का विकल्प चुना था। आवश्यक सेवाओं में तैनात 12 डी भरने वाले 641 मतदाताओं में से भी 390 मतदाता 27 मई तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं।

नड्डा हिमाचल के हितों की पैरवी करने में रहे नाकामःरोहित

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने घर हिमाचल प्रदेश में केवल राजनीतिक पर्यटक बन कर रह गए हैं। चुनाव के दिनों में वह हिमाचल के लोगों से वोट मांगने के लिए आते हैं और इतने बड़े पद पर रहते हुए भी वह दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करने में नाकाम रहे हैं।

रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले मानसून सीज़न में हिमाचल प्रदेश में आई सबसे बड़ी आपदा के दौरान नड्डा आपदा प्रभावित परिवारों को केंद्र सरकार से एक पैसे की भी विशेष मदद दिलाने में नाकाम रहे, जबकि इस आपदा में 550 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और राज्य को 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद भी कम हुई है। केंद्र से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को घटाकर कर 1800 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसे अगले वर्ष और कम कर दिया जाएगा। यही नहीं, जीएसटी कंपोनेंट के अंतर्गत प्रति वर्ष मिलने वाली 2500 करोड़ रुपए की धनराशि भी बंद कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर हिमाचल प्रदेश के लिए ऋण लेने की सीमा 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे 1700 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक्टर्नल एडेड प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र सरकार ने तीन साल में 3000 करोड़ रुपए की लिमिट तय कर दी है। सेंट्रल ट्रांसफर के भाजपा सरकार के कार्यकाल में मिलने वाले 4151 करोड़ को घटाकर 3395 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की भी पैरवी भी नहीं की। अन्यथा आयात शुल्क को तीन गुणा बढ़ाने की जगह मोदी सरकार इसे कम करके 50 प्रतिशत नहीं करती। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क घटाने से देश में सेब का रिकॉर्ड आयात हुआ है और प्रदेश के बागवानों पर मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सेब का कंसंट्रेट को जूस में मिलाकर बागवानों को समृद्ध बनाने की बात कही थी, लेकिन यह बात भी जुमला ही साबित हुई है। इसके अतिरिक्त एमआईएस के तहत 50:50 के अनुपात में मिलने वाली आर्थिक सहायता को बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर केंद्र सरकार से केवल एक लाख रुपए टोकन मनी दिया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं और उन्हें इन बातों पर राज्य के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के सामने रखना चाहिए था, लेकिन वह दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं।

बुजुर्गों सहित नए वोटर्स ने दिखाया मतदान को लेकर उत्साह

शिमला/शैल। मतदान केंद्रों पर वोट डालने को लेकर 80 प्लस बुर्जुगों का उत्साह देखते हुए बनता है इसके साथ ही नए वोटर्स का जोश भी चुनाव का पर्व देश के गर्व का एहसास करवा गया। भीषण गर्मी भी बुजुर्गो के मतदान के जज्बे को कम नहीं कर पायी है। दरंग के 85 वर्षीय बुर्जुग प्रकाश ने होम वोटिंग के विकल्प की जगह मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला वहीं 81 वर्षीय मनोरमा गुलेरिया, 76 वर्षीय कौशल्या देवी ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसी तरह से फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए अपने मत का प्रयोग किया। गौरतलब है कि कांगड़ा जिला 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का नाम मतदाता सूची दर्ज करने में पूरे प्रदेश में सबसे आगे है। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाताओं के 32369 नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैं। राज्य में 31 दिसंबर से लेकर 4 मई तक राज्य में 18 से 19 आयु वर्ग के नए मतदाताओं के 92136 नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं जिसमें कांगड़ा जिला 32369 नए मतदाताओं के नाम जोड़ कर सबसे अव्वल रहा है

जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

एनडीए का चार सौ पार होना संदिग्ध

अंतिम चरण के मतदान के साथ ही एग्जिट पोल के परिणाम आने शुरू हो गये हैं। इन परिणामों में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी दावे के साथ इण्डिया गठबंधन में भी अपनी बैठक के बाद गठबंधन को 295 सीटें मिलने का दावा किया है। मोदी ने इस चुनाव के लिए चार सौ पार का लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा था। एक एग्जिट पोल में मोदी की जीत का आंकड़ा 401 भी दिया गया है। यदि 2014 और 2019 के चुनावी परिदृश्य पर नजर दौड़ायें तो स्पष्ट हो जाता है की तब के चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के अनुमानों से मिलते जुलते ही रहे हैं। उसी तर्ज पर इस बार भी एग्जिट पोल सही सिद्ध होते हैं या नहीं इसका पता तो 4 जून को परिणाम आने के बाद ही लगेगा। चुनाव सरकार के कामकाज की समीक्षा होते हैं और यह आकलन हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है। पिछले दोनों चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठे हैं। ईवीएम पर सबसे पहले एक समय भाजपा ने ही सवाल उठाए हैं। इस बार भी ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था जिस पर इन चुनावों के दौरान फैसला आया है। अभी भी चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे में ईवीएम का मुद्दा इस बार के परिणामों के बाद भी उठता है या नहीं यह देखना रोचक होगा।

मोदी पिछले दस वर्षो से केंद्र की सत्ता पर काबिज है। इसलिये इन दस वर्षो में जो भी महत्वपूर्ण घटा है और उससे आम आदमी कितना प्रभावित हुआ है उसका प्रभाव निश्चित रूप से इन चुनावों पर पड़ा है। महत्वपूर्ण घटनाओं में नोटबंदी, षि कानून और उनसे उपजा किसान आंदोलन तथा फिर करोना काल का लॉकडाउन ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने हर आदमी को प्रभावित किया है। इसी परिदृश्य में काले धन की वापसी से हर आदमी के खाते में पन्द्रह-पन्द्रह लाख आने का दावा भी आकलन का एक मुद्दा रहा है। हर चुनाव में किये गये वायदे कितने पूरे हुये हैं यह भी सरकार की समीक्षा का मुख्य आधार रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव में हर चरण के बाद मोदी ने मुद्दे बदले हैं। कांग्रेस पर वह आरोप लगाये हैं जो उसके घोषणा पत्र में कहीं दर्ज ही नहीं थे। बल्कि मोदी के आरोपों के कारण करोड़ों लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को डाउनलोड करके पड़ा है। राम मंदिर को इन चुनावों में केंद्रीय मुद्दा नहीं बनाया जा सका। इसी तरह इस चुनाव में आरएसएस और भाजपा में बढ़ता आंतरिक रोष जिस ढंग से भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साक्षात्कार के माध्यम से सामने आया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बार भाजपा का आंकड़ा पहले से निश्चित रूप से कम होगा। क्योंकि जिन राज्यों में पिछली बार पूरी पूरी सीटें भाजपा को मिली है वहां अब कम होंगी और उसकी भरपाई अन्य राज्यों से हो नहीं पायेगी।

इसी तर्ज पर इंडिया गठबंधन पर यदि नजर डाली जाये तो इस गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल है। तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार हैं। लेकिन इन राज्यों में भी कांग्रेस सारी सारी सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि इन सरकारों की परफार्मेस अपने-अपने राज्यों में ही संतोषजनक नहीं रही है। फिर चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों का चुनाव लड़ने से इन्कार और भाजपा में शामिल हो जाना ऐसे बिन्दु हैं जिसके कारण कांग्रेस अपने को मोदी भाजपा का विकल्प स्थापित नहीं कर पायी है। इसलिए इण्डिया गठबंधन के सरकार बनाने के दावों पर विश्वास नहीं बन पा रहा है। जो स्थितियां उभरती नजर आ रही है उससे लगता है कि विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत और प्रभावी भूमिका में रहेगा।

चुनाव में आखिर मुसलमानों का एजेंडे क्या होना चाहिए?

गौतम चौधरी

चुनावी मौसम चल रहा है। एक जून को अंतिम चरण का चुनाव होना है। देश के कई हिस्सों में अधिकतर स्थानों पर चुनाव हो भी चुके हैं। 2024 का संसदीय आम चुनाव अपने में कई विशेषता को समेटे हुए है। ऐसे में मुसलमानों को भी अपनी चुनौतियों को लेकर चुनाव से संबंधित एजेंडा तय करना चाहिए, जो पूरे चुनाव देखने को नहीं मिला। इस चुनाव में अधिकतर मुसलमान एक खास पार्टी के खिलाफ अपना एजेंडा सेट करते रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि भारत के मुसलमान चुनाव को लेकर उतने संवेदनशील नहीं है, जितने अन्य समुदाय के लोग हैं।

राजनीतिक दल चुनावी अभियानों में मतदाताओं के व्यवहार और विचार को प्रभावित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सतही तौर पर देखें तो पिछले कई अन्य चुनाव की तरह इस चुनाव में भी भारतीय राजनीति अक्सर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक बहस से प्रभावित है। चुनाव प्रचार का रंग भी सांप्रदायिक हो रखा है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि नफरत से प्रेरित लोग अक्सर इन विभाजनकारी आख्यानों में फंस जाते हैं लेकिन समझदार हमेशा ऐसी खोखली बयानबाजी के पीछे की मूर्खताओं को जानते हैं। इसलिए ऐसे मौकों पर अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपना एजेंडा तय करना चाहिए न कि नाहक के बहस में अपना समय खराब करना चाहिए।

राजनीतिक दलों से आश्वासन लेना और समाज की जरूरतों पर उनके साथ मोलभाव करना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए चुनाव के समय प्रभावी अभिव्यक्ति और एजेंडा निर्धारण की आवश्यकता होती है। सच तो यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज का विकास तभी संभव होता है जब वह अपने आप को जागरूकता की कसौटी पर कसता है। इसके लिए उस समाज को चुनावी प्रक्रिया में तो भाग लेना ही चाहिए साथ ही अपने समुदाय के उन्नयन के लिए वास्तविक मुद्दों पर मतदान करने का अभियान भी चलाना चाहिए।

भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रमुख घटक मुसलमानों के लिए प्रमुख चिंताओं में से एक व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर हाशिए पर रहने के साथ उनका पिछड़ापन है। इसे चुनाव अभियानों में एक मुद्दा बनाया जा सकता था लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उदाहरण के लिए, चुनावी मौसम के दौरान, मुस्लिम समुदाय उम्मीदवारों से अल्पसंख्यक समूहों की भलाई के उद्देश्य से स्पष्ट नीतियों और पहलों को स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं। मुस्लिम समुदाय को आर्थिक विकास और रोजगार के क्षेत्र में राजनीतिक नेताओं का समर्थन लेना चाहिए। शिक्षा और कौशल विकास, मुस्लिम समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। शिक्षा के लिए संसाधनों का समर्पण, जैसे छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी और न्यायसंगत कार्यान्वयन और प्रशिक्षण पहल के लिए धन का आवंटन, अल्पसंख्यक केंद्रित संस्थानों की स्थापना, नौकरियों में आरक्षण या पसमांदा के लिए आरक्षण का विस्तार मुस्लिम समुदाय और राजनीतिक दलों के बीच सौदेबाजी का मसौदा हो सकता है। इस पूरे चुनाव ये तमाम मुद्दे गौन रहे।

इससे नियोक्ताओं की आवश्यकताओं और मुस्लिम समुदायों के भीतर नौकरी चाहने वालों की क्षमताओं के बीच अंतर को पाटने में मदद मिलती। आवश्यक योग्यता और अनुभव की कमी के कारण, कई मुसलमानों को अक्सर सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिल पाती है। इससे समुदाय के भीतर आर्थिक असुरक्षा और असमानता पैदा होती है। ऐसी नीतियों और पहलों की मांग बढ़ रही है, जो इन विसंगतियों से निपटें और मुसलमानों को नौकरी बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद पहुंचा सकता है। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश मुस्लिम समुदायों को आर्थिक सफलता और स्थिरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने और बेहतर आर्थिक स्थिति में ले जाने में मदद करेगा। मुस्लिम उद्यमी और व्यवसाय के मालिक भी अपने व्यवसाय को स्थापित करने और विस्तारित करने के लिए संसाधन और धन प्राप्त करने में सहायता की तलाश में रहते हैं, जिससे समग्र आर्थिक प्रगति और कल्याण में योगदान मिलता है। राजनीतिक नेताओं के सहयोग से मुस्लिम समुदाय उन नीतियों की वकालत कर सकते हैं, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उपयोगी होगा लेकिन इस प्रकार की बातें कहीं सुनने देखने को नहीं मिल रही है। मुस्लिम समाज का एक मात्र एजेंडा होता है भाजपा हराओ। इससे मुसलमानों का कल्याण होना नहीं है। इससे अन्य पार्टियां केवल मुसलमानों से फायदा उठाती है उन्हें कुछ भी देने से हिचकती है।

समुदायों के भीतर प्राकृतिक रूप से नेताओं का उभरना और इन मुद्दों से निपटने के लिए राजनीतिक दलों के साथ सहयोग करना और एक अधिक समावेशी समाज के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। यह भारतीय मुसलमानों के बीच प्रचलित राष्ट्रवादी उत्साह को एक नयी पहचान देगा। जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद, मुसलमान अक्सर खुद को हाशिए पर पाते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, राजनीतिक दलों को भी सकारात्मक पहल करते हुए मुस्लिम नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए और उनके अंदर निर्णय की क्षमता का विकास करना चाहिए। केवल यह सुनिश्चित करके कि निर्णय लेने में भारतीय मुसलमानों की सार्थक भूमिका हो, हम वास्तव में अधिक समावेशी और प्रतिनिधि लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि विभाजनकारी और अलग-थलग करने वाले कृत्य न तो देश के लिए अच्छा है और न मुसलमानों के लिए बढ़िया है। इससे किसी का भला होना नहीं है। साथ ही किसी पार्टी के प्रति नकारात्मका रवैया भी ठीक नहीं है। मुसलमानों को इस पर विचार जरूर करना चाहिए।

आम चुनाव 2024 में पहली बार पात्र मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा को देश भर में बढ़ाया गया

शिमला। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आम चुनाव 2024 में समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाये हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता शारीरिक या अन्य बाधाओं के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रहने पाये। अब तक, चुनाव के छः चरणों के पूर्ण होने के बाद, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) जैसे विभिन्न वर्गो के मतदाताओं के बीच अपार उत्साह देखा गया। आम चुनाव 2024 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40 प्रतिशत की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ पूरे देश में किये गये ठोस प्रयासों से उन राज्यों/ब केंद्र-शासित प्रदेशों से सफलता की कई कहानियां सामने आयी हैं, जहां लोकसभा चुनाव-2024 के छठे चरण तक चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सीईसी राजीव कुमार ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर नये मानक स्थापित करते हुये चुनावी प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करना आयोग का दृढ़ संकल्प रहा है। ईसीआई चुनावों को वास्तव में बहुलता और विविधता की भावना को प्रतिबिंबित करने वाला बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है, जो हमारे देश का गौरव है। ईसीआई पूरी चुनाव प्रक्रिया में समावेशिता व पहुंच के सिद्धांतों और प्रथाओं को शामिल करने और गहराई से एकीकृत करने के लिए समर्पित है, ताकि समाज के सामने हर जगह अनुकरण के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके।

मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के पंजीकरण और अद्यतनीकरण के लिए दो साल पहले से ही ठोस प्रयास किए जा रहे थे। इन श्रेणियों के मतदाताओं को लक्षित कर विशेष पंजीकरण अभियान, शिविर आयोजित करके यह लक्ष्य हासिल किया गया। ईसीआई ने उन समुदायों के बीच भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जो अपने मतदान के अधिकार से वंचित होने की संभावना रखते हैं।

घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा चुनावी प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है और इसे भारत के आम चुनावों के इतिहास में पहली बार उपलब्ध कराया गया है। 85 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी पात्र नागरिक या 40 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाला व्यक्ति इन चुनावों में डाक मतपत्र के माध्यम से घर से मतदान सुविधा का लाभ उठा सकता है। इस सुविधा को मतदाताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। मुस्कुराते हुए मतदाताओं और उनके घर से आराम से मतदान करने के उनके प्रशंसापत्रों के सुखद दृश्य देश के सभी हिस्सों से सोशल मीडिया पर छा गए हैं। घर से मतदान, मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की पूरी टीम की भागीदारी के साथ होता है और मतदान की गोपनीयता को पूरी तरह बनाए रखा जाता है। उम्मीदवारों के एजेंटों को भी मतदान प्रक्रिया देखने के लिए पोलिंग टीम के साथ जाने की अनुमति है।

किसी भी बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए, ईसीआई ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र भूतल पर हो, जिसमें रैंप, मतदाताओं के लिए साइनेज, पार्किंग स्थल, अलग कतारें और स्वयंसेवकों सहित सुनिश्चित सुविधाएं हों। इसके अलावा, ईसीआई के सक्षम ऐप ने दिव्यांगों को मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर, पिक-एंड-ड्रॉप और स्वयंसेवकों की सेवाओं जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान की है। चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक, सक्षम ऐप के 1.78 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं।

चुनाव आयोग ने दृष्टिबाधित मतदाताओं की सहायता के लिए ईवीएम पर ब्रेल, ब्रेल सक्षम ईपीआईसी और मतदाता पचह्न के लिए भी प्रावधान किए हैं। इसके अलावा, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंग्रेजी व हिंदी में एक मतदाता मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई, जिसमें पंजीकरण से लेकर मतदान दिवस तक की सुविधा की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

मतदान में शारीरिक बाधाओं को दूर करने के अलावा, चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर, पीवीटीजी जैसी कुछ कमज़ोर आबादी के इर्द-गिर्द सामाजिक बाधाओं और कलंक को दूर करने के लिए भी प्रयास किए, ताकि चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। नागरिक समाज के सहयोग से ठाणे जिले द्वारा थर्ड जेंडर (टीजी) मतदाताओं और सेक्स वर्कर व पीवीटीजी जैसे अन्य हाशिए के समुदायों को नामांकित करने के लिए विशेष शिविरों की व्यवस्था की गई थी। पूरे देश में 48,260 से ज्यादा टीजी नामांकित हैं, जिनमें से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 8,467 थर्ड जेंडर मतदाता हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 6,628 और महाराष्ट्र में 5,720 टीजी हैं।

एसवीईईपी पहल के हिस्से के रूप में, आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के बीच मतदाता जागरूकता पैदा करने और समावेशी चुनावों को बढ़ावा देने के लिए आईडीसीए (भारतीय बधिर क्रिकेट संघ) और डीडीसीए (दिल्ली जिला क्रिकेट संघ) टीमों के बीच 16 मार्च, 2024 को एक टी-20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया।

आयोग द्वारा यथासंभव प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसका प्रबंधन विशेष रूप से दिव्यांग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव-2024 के लिए, देश भर में लगभग 2697 दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 302 दिव्यांग मानवयुक्त मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

बेघर और अन्य घुंमतू समूह उच्च चुनावी भागीदारी हासिल करने में एक और महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी हैं। अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण, ये व्यक्ति निवास के प्रमाण की कमी के कारण अनजाने में चुनावी बहिष्कार का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि, पिछले दो वर्षो में उनके मतदाता के रूप में नामांकन और मतदान प्रक्रिया में भागीदारी के लिए विशेष प्रयास किए गए। पहले दुर्गम क्षेत्रों में नए मतदान केंद्रों ने बड़े पैमाने पर पीवीटीजी को शामिल किया है। कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां पीवीटीजी बड़ी संख्या में रहते हैं, पीवीटीजी को दूरदराज के क्षेत्रों से मतदान केंद्रों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। एक ऐतिहासिक कदम के तहत, ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव-2024 में मतदान किया।

चुनावी जागरूकता को बढ़ावा देने और चुनावों में भागीदारी व समावेशिता की भावना पैदा करने के लिए, चुनाव आयोग ने ग्यारह दिव्यांग व्यक्तियों को 'ईसीआई एंबेसेडर' के रूप में नामित किया है, ताकि समुदाय को चुनावी प्रक्रिया में और अधिक शामिल किया जा सके। मतदान कर्मियों को दिव्यांगों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया गया है, ताकि चुनावों में भागीदारी और स्वामित्व की भावना विकसित की जा सके। राज्य के सीईओ ने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित राज्यों के दिव्यांगता और स्वास्थ्य विभागों के साथ भी सहयोग किया।

इसके अलावा, ईसीआई अधिकारियों की एक टीम ने ठाणे जिले और मुंबई शहर के कमाठीपुरा का दौरा किया, ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले ट्रांसजेंडर और महिला यौनकर्मियों के साथ खुली बातचीत की जा सके, ताकि चुनावी भागीदारी में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके, इन मतदाताओं के प्रति फील्ड मशीनरी को संवेदनशील बनाया जा सके और इन मतदाताओं को लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं को लोकसभा चुनाव-2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा तीरंदाज सुश्री शीतल देवी को 'ईसीआई नेशनल आइकन' नियुक्त किया है। साथ ही, ईसीआई की विभिन्न मतदाता जागरूकता पहलों में भाग लेने और दिव्यांग मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ग्यारह प्रमुख दिव्यांग हस्तियों को ईसीआई का एंबेसेडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, आयोग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य दिव्यांग आइकन भी नियुक्त किए हैं।

आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 'कोई भी मतदाता पीछे न छूटे' और उसने देश के सुदूर कोनों में रहने वाले मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विशेष उपाय किए हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात के अलियाबेट में एक शिपिंग कंटेनर में एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया, ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय मतदाताओं तक पहुंचा जा सके। इसी तरह, छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर संसदीय क्षेत्रों के 102 गांवों के मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने गांव में स्थापित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला।

इसके अलावा, चल रहे आम चुनाव 2024 में कश्मीरी प्रवासियों द्वारा मतदान की सुविधा के लिए एक बड़े फैसले में, भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले घाटी के विस्थापित लोगों के लिए फॉर्म-एम भरने की जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, जम्मू और उधमपुर के बाहर रहने वाले प्रवासियों (जो फॉर्म एम जमा करना जारी रखेंगे) के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-एम के साथ संलग्न प्रमाण पत्र के स्व-सत्यापन को अधिकृत किया है, इस प्रकार इस प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराने की परेशानी को दूर किया है। आयोग ने दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के विभिन्न राहत शिविरों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को भी नामित विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने या डाक मतपत्र का उपयोग करने का विकल्प दिया है। जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए।

इसी तरह, मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के लिए मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 10 जिलों में 94 विशेष मतदान केंद्र (एसपीएस) स्थापित किए गए। टेंग्नौपाल जिले में एक मतदाता के लिए एक विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया गया। मतदान वेबकास्टिंग/वीडियोग्राफी के तहत आयोजित किया गया और राहत शिविरों के बाहर रहने वाले विस्थापित व्यक्ति भी एसपीएस में मतदान करने का विकल्प चुन सकते थे।

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव में शामिल सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया

शिमला। भारत ने इतिहास रच दिया है। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान शुरू होने और 7 चरणों के साथ आम चुनाव 2024 के लिए मतदान संपन्न हो गया। देश के मतदाताओं ने 18वीं लोकसभा के गठन के लिए मतदान करने का अपना सबसे प्रिय अधिकार का इस्तेमाल किया है। भारतीय लोकतंत्र और भारतीय चुनावों ने फिर से जादू कर दिया है। महान भारतीय मतदाताओं ने अपनी जाति, पंथ, धर्म, सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि से परे जाकर एक बार फिर यह कर दिखाया है। वास्तव में असली विजेता भारतीय मतदाता हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू और भारत निर्वाचन आयोग परिवार मतदाताओं के प्रति बहुत आभारी हैं, जिन्होंने कई चुनौतियों और दुविधाओं को पार करते हुए मतदान केंद्र तक पहुंचने में सफलता पाई। निर्वाचन आयोग ने पूरी ईमानदारी से सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी प्रशंसा की है। अपनी जबरदस्त भागीदारी के माध्यम से, मतदाताओं ने भारतीय संविधान के संस्थापकों द्वारा व्यक्त विश्वास को पूरा किया है, जब उन्होंने आम भारतीय को मताधिकार का अधिकार सौंपा था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की व्यापक भागीदारी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और भावना की पुष्टि करती है।

भारत निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा बलों सहित पूरी चुनाव मशीनरी के प्रति भी आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने देश भर में मतदाताओं को सुचारु, शांतिपूर्ण और उत्सव का माहौल प्रदान करने, प्रतिकूल मौसम, दुर्गम इलाकों जैसी चुनौतियों का सामना करने और विविधतापूर्ण जनसंख्या के बीच कानून व व्यवस्था का प्रबंधन करने में समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाई।

आयोग सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का भी आभार व्यक्त करता है, जो भारतीय चुनावों की महत्वपूर्ण केन्द्र-बिन्दु हैं।

आयोग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के योगदान के लिए भी आभारी है। आयोग ने हमेशा मीडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए सहयोगी माना है।

शतायु, बुजुर्गो, दिव्यांगजनों और थर्ड जेंडरों द्वारा डाले गए वोटों का महत्व कई लोगों, खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो लोकतंत्र को और आगे ले जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की इच्छा है कि भारत की अगली पीढ़ी के मतदाता इस भागीदारी को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

मतदान के दौरान मतदाताओं, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों के सामूहिक प्रयासों ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, जो बहुत सम्मान और प्रशंसा के योग्य है। देश के लोगों ने सामूहिक प्रयासों के बल पर लोकतंत्र के चक्र को निरंतर सक्रिय रखा है।

मोदी-शाह ने धनबल से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की

शिमला/शैल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जोरदार जुबानी हमला बोला। उन्होंने ऊना जिले के गगरेट में चिंतपूर्णी माता और भगवान भोलेनाथ के जयकारे

के साथ अपने भाषण की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि भाजपा का धर्म सिर्फ सत्ता और संपत्ति है। मोदी और शाह ने धनबल से प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। मोदी ने अपने खरबपति मित्रों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसानों की कर्ज माफी के लिए उनके पास पैसा नहीं है।

प्रियंका ने कुटलैहड़ विधानसभा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भोटा और बड़सर बाजार में रोड शो निकाला, जिसमें अपार जनसमर्थन मिला। प्रियंका ने लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा, विधानसभा उम्मीदवार राकेश कालिया, विवेक शर्मा और सुभाष ढटवालिया के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि आज भी भाजपा हिमाचल की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में लगी हुई है। हमारे नेताओं की दृढ़ता व एकजुटता है कि हम आज भी सरकार चला रहे हैं। जिन्होंने जाना था अच्छा है चले गए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। आपदा व सरकार गिराने के प्रयासों के समय भाजपा का सच जनता के सामने आया। मोदी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक काम नहीं करते। जनता के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है। भाजपा वाले कौन से धर्म के रखवाले हैं, जो धनबल से सरकारों को गिराते हैं, विधायकों को करोड़ों रुपये में खरीदते हैं। आपदा में साथ नहीं देते। मोदी कैसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हिमाचल में आपदा को पूरी तरह नकार दिया।

प्रियंका ने कहा कि भाजपा दस साल में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। यह कैसे हुआ, जानना जरूरी है, बड़ी-बड़ी कंपनियों को डरा धमकाकर कर चंदा लिया गया। हिमाचल में 6-6 उपचुनाव करा रहे हैं, जिनमें करोड़ों रुपये खर्च करेंगे, लेकिन आपदा में देने के लिए पैसे नहीं। मोदी सरकार ने दस साल जनता को गुमराह करने का ही काम किया। हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। प्रदेश सरकार ने अपने कोष से 22000 प्रभावित परिवारों को फिर से बसाया। लेकिन, मोदी सरकार ने एक रुपया नहीं दिया। आर्थिक संकट के बावजूद 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दी, 18 साल से अधिक आयु की बेटियों, महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन दी जा रही है। दूध पर एमएसपी देने वाला हिमाचल पहला राज्य है, यहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू लोगों के साथ घुलमिलकर रहते हैं। आपदा में आपने उनका काम देखा है।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर जनता को नहीं दिखते। वह दिल्ली में सूट-बूट में अपने खरबपति मित्रों के साथ ही नजर आते हैं। मोदी भी ऐसे हैं, वह भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी नहीं जाते। इनकी विचारधारा अलग ही है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी घर-घर जाकर लोगों की समस्याओं को जानती थी, लोग डांट भी देते थे, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। आज के प्रधानमंत्री कोई डांट के दिखाए। एक तरफ देश के साथ घुलने-मिलने की विचारधारा है, तो दूसरी तरफ 100-100 करोड़ रुपये लगाकर कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने की। मोदी के राज में देश में लोकतंत्र का नामोनिशान नहीं है। देश में 70 करोड़ बेरोजगार हैं। अग्निवीर जैसी योजनाएं युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर रही हैं। कांग्रेस सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना को बंद करेगी। मनरेगा की दिहाड़ी 400 रुपये प्रतिदिन होगी। शहरी मनरेगा शुरू करेंगे। छोटे व्यापार को मजबूत बनाया जाएगा। हिमाचल की जनता 1 जून को जागरूक होकर वोट करे। चारों लोकसभा व 6 विधानसभा सीटों को जिताइये, इससे देशभर में यह संदेश जाना चाहिए कि देवभूमि की जनता धनबल की राजनीति बर्दाश्त नहीं करती। यहां के लोग पवित्र और शालीन हैं, उनमें सभ्यता का अहसास होता है। मेरा भी हिमाचल में घर है। लोग साधारण जीवन जीते हैं, झूठ में अधिक नहीं पड़ते। पिछले डेढ़ साल से कांग्रेस की सरकार ने जनता की सेवा की है, लेकिन भाजपा इसे पचा नहीं पा रही। हमारे सारे नेता जनसेवा में लगे हैं जबकि भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी राजनीति कर रहे हैं, आपदा तक में हिमाचल की सुध नहीं ली।

अनुराग बतायें तलवाड़ा-हमीरपुर में कब पहुंचेगी रेलःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सतपाल रायजादा के अलावा गगरेट, कुटलैहड़ व बड़सर में राकेश कालिया, विवेक

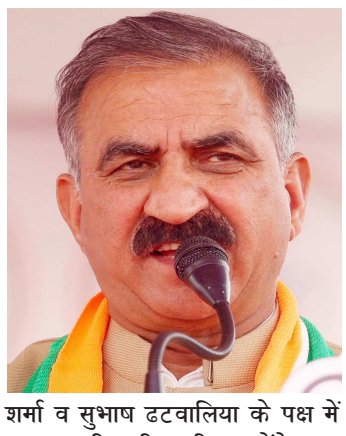

शर्मा व सुभाष ढटवालिया के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर 20 साल सांसद जीतकर जा रहे हैं, लेकिन न तो ऊना से तलवाड़ा तक रेल लाइन पहुंची न ही हमीरपुर तक। अनुराग झूठ के सहारे अपनी राजनीति चला रहे हैं। मोदी व अनुराग ने दस साल पहले कहा कि एक साल में रेल लाइन तलवाड़ा पहुंच जाएगी, वे जनता को बताएं कि अब फाइल क्यों दबी हुई है। लोकतंत्र में जनबल सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए भाजपा के झूठ व धनबल को जनता 1 जून को करारा जवाब दे। गांधी परिवार का हिमाचल के साथ गहरा नाता है। इंदिरा गांधी ने हिमाचल को अलग राज्य बनाया। सोनिया गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया आजकल कोई प्रधान व पंच का पद नहीं छोड़ता। भाजपा झूठ पर झूठ परोसने में लगी हुई है। लेकिन, उसका चाल, चेहरा व चरित्र बेनकाब हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गगरेट में चाय, पकौड़े वालों, पेट्रोल पंप, ढाबों व दुकानों पर चैतन्य टैक्स लगा हुआ था। कोई अफसर गगरेट आने को तैयार नहीं था, एक अफसर ने तो मुझे कहा कि काजा भेज दो पर गगरेट मत भेजो। अफसर कमीशन के पैसे एकत्रित करने को तैयार नहीं थे। बिकाऊ विधायक चैतन्य का लक्ष्य हर साल 15 करोड़ रुपये कमाने का था, जो हमारी सरकार के भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बन्द करने के कारण संभव नहीं था। भाजपा जितना मर्जी जोर लगा ले यह सरकार पांच साल चलेगी और जनसेवा काम बदस्तूर जारी रहेगा। न तो भाजपा ओपीएस छीन सकती है न ही महिलाओं की 1500 रुपये पैन्शन रुकवा पाएगी।

एग्जिट पोल का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीः राठौर

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते

हुए कहा है कि यह पूरी तरह तथ्यों से विपरीत और भाजपा के कार्यालय में बना कर मीडिया को वितरित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नही है और भाजपा द्वारा यह देश मे सनसनी फैलाने व चुनाव से जुड़े अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुये कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री का 400 पार का नारे को जिस प्रकार से मीडिया में प्रचारित किया गया और अब एग्जिट पोल में उसे साबित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में कही भी भाजपा के प्रति कोई उत्साह नही देखा गया, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी व बढ़ती मंहगाई जैसे मुद्दों पर कोई बात नही की। ऊलजलूल बाते कर लोगों में भ्रम पैदा करने व साम्प्रदायिक ध्रुविकरण करने की पूरी कोशिश की गई।

राठौर ने कहा कि एग्जिट पोल का क्या आधार था, कब और कहा किया गया, कितने लोगों से बात की गई सेंपल, इस सब की जानकारी एग्जिट पोल करने वाली कम्पनियों को लोगों को देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में बहुत सी विसंगतियां है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एग्जिट पोल से सनसनी नही फैलाई जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगे।

राठौर ने कहा कि कांग्रेस देश के लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से लोकतंत्र का हनन व संविधान की अवहेलना भाजपा द्वारा की जा रही है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर उन्हें डराने व अपने पक्ष में करने के बाद उन्हें आरोपों से वरी कर देना भाजपा की नीति रही है। राठौर ने कहा कि चुनाव नतीजे एग्जिट पोल के विपरीत पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे और कल ईवीएम के खुलने से साफ हो जाएगा।

देश कि राजनीति की दशा व दिशा तय करेंगे यह चुनाव परिणामः मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की चारों लोकसभा व छः विधानसभा उप चुनावों में कांग्रेस की प्रचंड जीत होने जा रही है। उन्होंने कहा है कि

लोगों को भाजपा के धनबल पर नही कांग्रेस के जनबल पर विश्वास है। षडयंत्रकारियों को इस बार प्रदेश के लोग सबक सिखाएगें।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ननखड़ी व कुल्लू जिला के निरमंड में विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में बड़ी चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह प्रदेश का भविष्य है और उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित व सवारना होगा। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह भारी मतों से जीत रहें है बस देखना अब यह है कि उनकी जीत कितने रिकार्ड तोड़ मतों से होती है। उन्होंने दावा किया कि कंगना न तो विधानसभा और न ही लोकसभा की चौखट कभी लांग सकेंगी। उन्होंने कहा कि स्व. वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में अथाह विकास कार्य किये है उसमें ननखड़ी भी है। उन्होंने लोगों का आहवान किया कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र से एकतरफा विक्रमादित्य सिंह को ही वोट आने चाहिए। यही उनकी वीरभद्र सिंह के लिये सच्ची श्रद्धांजलि होंगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि कंगना के पीछे भाग भाग कर अब वह थक चुके हैं। कंगना का 4 जून का मुंबई जाने का टिकट बुक हो चुका है। उन्होंने कहा कि कंगना भी अपनी हार को देखकर बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना को फिल्मी दुनिया में ही रहकर अपना नाम कमाना चाहिए बाकी मण्डी संसदीय क्षेत्र के लिये विक्रमादित्य सिंह ही बहुत है।

मुकेश ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है इस कृत्य का परिणाम प्रदेश के लोग उसे 2 जून को देने जा रहें है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ओर भी मजबूत होकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को कोई भी खतरा नही है यह सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद फिर से अपनी सरकार बनाएगी।

विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान कहा कि सांसद बनने के बाद ननखड़ी में केंद्र सरकार का एक बड़े फल विधायन सयंत्र केंद्र की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त यहां एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मण्डी संसदीय क्षेत्र के विकास के विजन को लेकर वह इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में मण्डी शहर को शिमला व धर्मशाला की तरह स्मार्ट सिटी बनाना, कुल्लू में मेडिकल कालेज की स्थापना भुभु व जलोड़ी जोत पर सुरंग का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के पास न तो कोई विजन है और न ही कोई सोच। उन्होंने कहा कि मोदी के नाम का जाप कर वह वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि जिस अभद्र भाषा का वह अपने मंचो से उनके लिये प्रयोग करती है वह भाषा प्रदेश कि किसी बेटी की कभी नही हो सकती।

आगजनी की घटनाओं पर की चिंता व्यक्त

कुलदीप सिंह राठौर ने आजकल गर्मी के दिनों में जंगलों में लग रही आग की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि वन विभाग के अधिकारियों को इस पर काबू पाने के लिये कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आगजनी से एक ओर जहां प्राकृतिक आपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है वही पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है।

राठौर ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात कर अपनी इस चिंता से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिन बागवानों के बाग इस आगजनी से नष्ट हो गये है या जिनके घर आग की इस चपेट में आये है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

राठौर ने कहा कि जिन इलाकों में पेयजल समस्या हो रही है उन जगहों पर टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

हिमाचल में पूरे होंगे रोप-वे व सुरंगों के कार्य: नितिन गडकरी

शिमला/शैल। अपने हिमाचल के दो दिवसीय चुनावी दौरे में सड़कें अच्छी होगी तभी हम विकास के मापदंडों पर खरा उतर पाएंगे आज चारधाम में देश तीन गुना से ज्यादा संख्या में लोग देख रहा है तो इसका कारण मात्र चारधाम

प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने 12,000 करोड़ के विश्वस्तरीय हाई-वे है जिस कारण तीर्थाटन व पर्यटन को बढ़ावा मिला है अच्छी सड़कें स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार स्वच्छ जल यह विकास के कुछ मूल है जिसपर की हमारी सरकार 10 सालों से कार्य कर रही है। आज हमारी सरकार ने देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक विश्वस्तरीय सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया है जिससे कि देश के नागरिकों के संसाधनों का बचाव हो रहा है साथ ही किसी भी राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस देश की सड़कों पर निर्भर करता है। आज हमारी सरकार ने ग्रीन हाईवे, ग्रीन कोरीडोर जैसे विचार इस विकास यात्रा में राष्ट्र को समिर्पत किए है। आज देश के नागरिक एक्सीस कन्ट्रोल सड़कों के माध्यम से पूरे देश भर कहीं आ जा सकते है। हिमाचल में भी बड़े स्तर पर हाइवे, रोपवे व केवल कार जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के लोगों को समृध एंव संपन्न बनाना चाहती हैं हिमाचल प्रदेश को अच्छी सड़के देना चाहती हैं। हम हिमाचल के नागरिकों को अच्छी आय के साधन प्रदान करना चाहते है व पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते है और यह सब केवल आपकी वोट की ताकत से ही संभव हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाजपा की देन है और देश के 6.50 लाख में से 4.50 लाख गाँव को इस योजना से जोड़ा गया था हिमाचल में भी 45,000 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर की सड़के ईसी योजना के अंतर्गत बनी आज हिमाचल में 1 लाख करोड़ के काम जारी है। हमने हिमाचल को बड़ी योजनाएँ जेसे किशाऊ बांध रेणुका जी बांध व लखवाड़ बांध जैसी बड़ी योजनाओं के साथ भी जोड़ा और अन्य राज्यों के साथ चल रहे संघर्षो को भी खत्म करने का प्रयास किया। आज देश का किसान 16 लाख करोड़ का बायो ईधन बना रहा है किसान मात्र अन्नदाता नही बल्कि ऊर्जादाता, ईंधनदाता भी बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से आज देश की दिशा बदल रही है पंजाब हरियाणा में पराली से सीएनजी बनाने का काम विदेश में हो रहा है।

उन्होंने कहा हमारी सरकार का उद्देश्य गरीबों की सेवा करना है आज देश हाथ से खींचने वाले रिक्शे को खत्म कर ई-रिक्शा की तरफ आगे बढ़ है और हम देश में इलैक्टिक ट्रैक्टर व इथानॉल ईधन से चलने वाले वाहनों का विचार देश को दिया आज देश में लगभग डेढ़ करोड़ ई-रिक्शा चल रहे है यही हमारी संवेदना है यही हमारा विचार है हमने 10 साल में टनलें रोड हाई-वे एयरपोर्ट हवाई अड्डों का निर्माण किया जिससे देश को तीव्र गति से आगे बढ़ाने और देश को विश्वस्तरीय सुविधायें प्रदान करने का प्रयास किया अभी तक जो देश ने विकास देखा व मात्र ट्रैलर था जिसकी फिल्म अभी बाकी है भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनेगा और यह केवल मुख्य धारा से पीछे रह गए लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ कर संभव है मैं कॉंग्रेस वालों को कहूँगा कि 60 साल में जीतने सड़कें हाई-वे इस देश में नही बने उतने हमने बना दिए।

उन्होंने कंगना के लिए समर्थन मानते हुए कहा की कंगना राष्ट्रवादी है राष्ट्र के लिए समर्पित है व हिमाचल की भूमि की पुत्री है और हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है अत: आप इन्हें संसद भेजे मंडी लोकसभा के विकास की गारंटी मैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते है।

संस्कृति विरासत को बढ़ाना और विकास दोनों मोदी के साथ ही संभव है:योगी

शिमला/शैल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत के पक्ष में हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के पक्ष में प्रचार के अंतिम दिन चुनाव प्रचार किया। कुल्लू में जनसभा को सम्बोधित करते हुई रैली कंगना की जमकर तारीफ़ की और उनकी तुलना मीराबाई से लेकर रानी पद्मिनी और रानी लक्ष्मीबाई से करते हुए कहा कि कंगना रनौत में मीराबाई के जैसी भक्ति हैं उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य और वीरांगना का भाव भी हैं। आपने देखा होगा कैसे इन्होंने मुंबई में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार को सड़को पर नाकों चने चबवा दिए थे। उन्होंने एक बार फिर 400 पार के नारे को दोहराते हुए दावा किया कि आज लोग कह रहे हैं जो राम लाये हैं हम उनको लायेंगे।

मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि अनुराग प्रधानमंत्री के नवरत्नों में से एक है और प्रधानमंत्री मोदी कि केबिनेट का एक स्मार्ट चेहरा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केबिनेट मंत्री पीयुष गोयल की बराबरी का गिना जाता है। विकास की एक एक योजना को देश को बताने का कार्य करते है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में बीते 10 साल में व्यापक बदलाव हुए है। सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, देश और प्रदेश भी वही था, मगर तब विकास की सोच नहीं थी। केवल अपने परिवार के विकास की सोच ही हावी थी। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अबकी बार चार सौ पार।

सीएम योगी ने कहा कि आज एक नई अयोध्या बन चुकी है, ऐसे लगता है जैसे प्रभु श्रीराम साक्षात

विराजमान होकर हमपर अपनी कृपा बरसा रहे है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके है, मगर उससे पहले ही वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। विश्रामालयों का नाम निषाद राज के नाम पर और माता शबरी के नाम पर भोजनालयों का नामकरण किया गया। हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है हमने रामलला को विराजमान होते देखा है। आप कह सकते हैं कि हमारे कारण ये काम हुआ है, जिसने भी कमल के फूल पर वोट दिया है। वह कह सकता है कि भगवान श्रीराम हमारे कारण विराजमान हुए है यह इस लोक और परलोक को सुधारने वाला कार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा 10 साल में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमने दुनिया में नई पहचान बनाई है। दुनिया में कहीं संकट आता है तो वह भारत की ओर देखती है।

प्रदेश में धधक रहे जंगल, सरकार चुनावों में व्यस्त:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। हिमाचल के जंगलों की आग निरंतर विकराल रूप ले रही है। वनों में लगी आग की वजह से शिमला और सोलन के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न इलाकों में वन संपदा को

नुकसान पहुंच रहा है। भाजपा पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश आग से हो रही घटनाओं से हिमाचल के जंगल धूं-धूं कर जल रहे है और प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी नहीं है अगर है तो इन घटनाओं को नज़रअंदाज कर रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि एक तो उनके पास इतना बड़ा मंत्रालय होने के बावजूद भी मंत्री नहीं है और मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद भी उस पर वे संवेदनहीन है। प्रदेश की जनता को ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है और मुख्यमंत्री को इस लापरवाही के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

प्रदेश सरकार के पास वन विभाग बहुत से उच्चाधिकारी हैं और बहुत स्टाफ होने के बावजूद भी वनों की ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। पिछली सरकार ने वन विभाग को सुविधाओं से भरपुर गाड़ियां सौंपी है और इनका उपयोग करना सरकार की जिम्मेवारी है। आग लगने के कारण वनों को नुकसान होने के साथ ही जीव जंतुओं और पर्यावरण पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि आग की वजह से जल स्त्रोत सूख रहे हैं, प्रदेश के धधकते जंगलों की आग की आंच का असर ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। भारद्वाज ने कहा कि जल, जंगल, जमीन हमारी धरोहर हैं, लेकिन हर साल जंगलों में आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। उन्होंने इसे आने वाले भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बताया है।

भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। झूठी घोषणाएं, गारंटियां व स्लोगन लिखकर सरकार बना तो ली लेकिन खुद के विधायक और जनता की जानमाल की सम्भाल नहीं कर पा रहे है। उन्होंने कहा कि वनो में बहुत से जीव-जन्तु मर रहे हैं और सरकार बेसुध, संवेदनहीन और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। प्रदेश के लोग आग से त्रस्त है, वन संपदा जल कर खाक हो गई है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 से 20 दिनों के अन्दर 31 जगह आग लगी। इसमें हमीरपुर में पंप हाउस, पीएचसी भी आग के हवाले हो गये। सोलन के जंगल भी पिछले एक सप्ताह से धधक रहे, कालका-शिमला ट्रैक के आसपास लगी आग जिससे प्रभावित होकर चार ट्रेनें रोकनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। हजारों हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र को नुकसान हुआ है। जीव-जंतु आग की भेंट चढ़ रहे हैं। 24 घंटे में प्रदेश के जंगलों में आग की 31 नई घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें कुल 302.98 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। अब तक कुल 9,480 हेक्टेयर वन क्षेत्र जला अब तक आग की घटनाओं का आंकड़ा 989 तक पहुंच चुका है। फायर सीजन खत्म होने में अभी आधा माह से ऊपर का समय बाकी है। इस सीजन में अब तक कुल 9,480 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। बिलासपुर सर्किल में जगलों में आग लगने की छ: घटनाएं वन विभाग ने दर्ज की हैं। चंबा में 1, धर्मशाला में 1, हमीरपुर में 2, मंडी में 8, नाहन में 5, शिमला में 5, रामपुर में 1, सोलन में 4 मामले जंगलों में आग लगने के सामने आए हैं। बिलासपुर सर्किल में 73.39 हेक्टेयर, चंबा में 5 हेक्टेयर, धर्मशाला में 2 हेक्टेयर, हमीरपुर में 13 हेक्टेयर, मंडी में 129.9, नाहन में 44 हेक्टेयर, शिमला में 23.8 हेक्टेयर, रामपुर में 0.5 और सोलन में 12 हेक्टेयर भूमि में वन संपदा राख हुई है। सोलन में लाखों की वनसंपदा राख, सुबाथू के साथ लगते जंगलों में आग से लाखों की वन संपदा जलकर नष्ट हो गई। आग सैनिक क्षेत्र के साथ लगते छपरौली गांव तक पहुंच गई, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई। इन सभी घटनाओं से पुन: प्रदेश में आपदा जैसे हालात हैं। पहले पानी ने तबाही मचाई अब आग प्रदेश को खोखला कर रही है जिससे प्रदेश सरकार जनता के मन से उतर गई हैं। प्रदेश को इतिहास में पहली बार निक्कमी व बेपरवाह सरकार मिली है।

पीएम मोदी का विजन विकसित भारत 2047

शिमला/शैल। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि पीएम मोदी देश की आवश्यकता है, मोदी के नेतृत्व में देश आगे बड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में चार लोकसभा चुनाव है और छ: उपचुनाव है, जो सारे के सारे चुनाव भाजपा जीतने वाली है। लोकसभा में चौका और विधानसभा उपचुनाव में छक्का लगना निश्चित है।

बिंदल ने कहा की वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि के आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत गति को दर्शाते हैं, जो आगे और भी तेज होने वाली है। देश के मेहनती लोगों के लिए धन्यवाद, जिनकी बदौलत 2023- 24 में विकास दर 8.2 प्रतिशत रही है। यह वृद्धि इस बात का भी उदाहरण है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ जैसा कि मैंने कहा, यह आने वाली चीजों का सिर्फ एक ट्रेलर है।

सरकार की तरफ से जारी किए गए वित्त वर्ष 2023-24 और जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के आर्थिक आंकड़े प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होने के दावे की तस्दीक करते हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 8.2 प्रतिशत रही, जो 2022-23 की सात प्रतिशत से ज्यादा है। जनवरी-मार्च, 2024 में विकास दर 7.8 प्रतिशत रही है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की 6.2 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, यह चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर 2023) की 8.6 प्रतिशत से कम है। आरबीआई ने एक दिन पहले ही कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक दशक तक तेज विकास दर हासिल करने के लिए तैयार है। सांख्यिकीय व कार्यक्रम क्रिन्यावयन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े इसी तरफ इशारा करते हैं। विकास दर के सभी आंकड़े आइएमएफ, विश्व बैंक सरीखी एजेंसियों के अनुमान से भी ज्यादा हैं। इन्हें फिर से भारतीय इकोनमी के लिए अपने अनुमानों में संशोधन करना होगा। ये आंकड़े बताते हैं कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन (रियल

जीडीपी) का आकार वर्ष 2023 24 में 173.82 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 160.71 लाख करोड़ रुपये था। इस आधार पर 8.2 प्रतिशत की विकास दर हासिल होने की बात कही गई है। जबकि चालू मूल्य पर आधारित जीडीपी (नामिनल) का आकार 296.50 लाख करोड़ रुपये आंका गया है और इसके हिसाब से 9.6 प्रतिशत की विकास दर हासिल की गई है। नामिनल जीडीपी के आकलन में वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमत और महंगाई, ब्याज दरों में बदलाव आदि जैसे मुद्दों को समाहित किया जाता है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

चुनाव के अन्तिम दिनों में वायरल हुये वीडियो ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल

- अप्रत्याशी नुकसान की आशंका बढ़ी
- आपदा राहत को लेकर दायर हुएआरटीआई आवेदनों का मकसद क्या है
- नड्डा के ब्यान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है इन आवेदनों को

शिमला/शैल। अन्तिम चरण का मतदान पूर्ण होने के बाद एग्जिट पोल के परिणाम आने शुरू हो गये हैं। इन परिणामों में एक न्यूज़ चैनल के एंकर ने दावा किया है कि कांग्रेस हिमाचल में चारों लोकसभा सीटें हार रही हैं और एक माह के भीतर प्रदेश सरकार गिर जायेगी। हिमाचल में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिये भी छः उपचुनाव हुये हैं। इस समय विधानसभा में आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस की संख्या 34 है और भाजपा की 25 है। तीन निर्दलीयों के त्यागपत्रों का मामला अभी लंबित चल रहा है। संभव है कि उनके बारे में जल्द ही फैसला आ जायेगा और दल बदल कानून के तहत निष्कासित हो जायेंगे। ऐसे में यदि छः उपचुनावों के परिणाम भाजपा के पक्ष में आ जाये तो भी भाजपा की संख्या 31 होगी और कांग्रेस की 34 और इस संख्या बल पर सरकार को इस समय कोई खतरा नहीं है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में अपनी चुनावी सभा में सरकार को लेकर टिप्पणियां की है उससे अवश्य यह संकेत उभरे हैं कि यदि केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में कुछ भी अप्रत्याशित देखने को मिल सकता है। क्योंकि हिमाचल से ही ताल्लुक रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आपदा राहत को लेकर एक चुनावी जनसभा में अवश्य कहा है कि वह इसमें सरकार से पूरा-पूरा हिसाब लेंगे।

इस चुनाव प्रचार में राज्य सरकार के नेतृत्व का केन्द्र के खिलाफ एक ही बड़ा आरोप रहा है कि केन्द्र ने हिमाचल की कोई सहायता नहीं की है। भाजपा इसका जवाब देती रही है कि प्रदेश सरकार ने आपदा राहत आवंटन में घोटाला किया है। अब इस आपदा राहत को लेकर दो लोगों ने सूचनाओं मांगी है। एक में जवाब मिला है कि केन्द्र से आपदा राहत में 1235.65 करोड़ मिला है और प्रदेश सरकार 2,27,75,00,000/- मिला है और आपदा राहत प्रकोष्ठ में 1,56,33,66,683/- शेष बचे हैं। यह जानकारी 29-4-2024 को दी गयी है। दूसरे आवेदन में सात बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। स्मरणीय है कि आपदा में प्रदेश के कर्मचारी पैन्शनरों, मंत्रियों, विधायको, सांसदों, अध्यक्षों आदि से भी योगदान लिया गया था। फिर कई राज्य सरकारों ने भी योगदान दिया है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 4800 करोड़ का राहत पैकेज दिया है। इस सब पर जानकारी मांगी गयी है। नड्डा के ब्यान के साथ इस जानकारी मांगने को देखा जा रहा है। इससे यह आशंका पुख्ता हो जाती है कि चुनाव परिणामों के बाद भाजपा सरकार को अस्थिर करने का प्रयास अवश्य करेगी।

इसी तरह चुनाव प्रचार के अन्तिम दिनों में हमीरपुर से एक वीडियो वायरल होकर लोगों तक पहुंचा है। इसमें हमीरपुर के एक बड़े कारोबारी के साथ सरकार के एक प्रभावशाली व्यक्ति के वार्तालाप की रिकॉर्डिंग है। इसमें कांगड़ा बैंक से 15 करोड़ के कर्ज को माफ करवाने के लिए 50 लाख मांगे जा रहे हैं। 18 लाख मिल चुके होने को स्वीकार भी किया जा रहा है। यह वायरल वीडियो प्रदेश के हर कोने तक पहुंचा हुआ होने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो पर किसी की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आयी है न ही इस वीडियो की प्रामाणिकता पर कोई सवाल उठाये गये हैं। चुनाव के अन्तिम दिनों में इस तरह की वीडियो वायरल होना निश्चित रूप से सरकार और कांग्रेस की चुनावी सेहत के लिये नुकसानदेह माना जा रहा है। भाजपा के कई नेताओं की साइट पर यह वीडियो देखा गया है। निश्चित रूप से इस वीडियो के सामने कांग्रेस के बगियों पर बिकाऊ विधायक होने का फतवा नहीं ठहर पाता है। इसी के साथ सुधीर शर्मा के आरोप आने वाली स्थितियों को बहुत गंभीर बना देते हैं। इसी परिदृश्य में यदि कांग्रेस का बड़ा चुनावी नुकसान हो जाये तो कोई हैरानी नहीं होगी।

सरकार की कठपुतली बन गये हैं विधान सभा अध्यक्ष:जयराम

शिमला/शैल। तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफ़े को स्वीकार करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शिमला से ब्यान जारी कर कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष को जब यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया। जान बूझकर पूरे मामले को लटकाया गया। जिससे तीनों निर्दलीय विधायक इसी आम लोकसभा और विधान सभा उप चुनावों में भाग न ले पाये। जिससे बहुत समय और संसाधन की बचत हो सकती थी। इस तरह से जानबूझकर किसी फ़ैसले को लटकाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर बैठे हैं लेकिन वह अपनी गरिमा के विपरीत काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सरकार की कठपुतली बन कर काम कर रहे हैं। इस तरह से पद की गरिमा के विपरीत वह क्यों काम कर रहे हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।

जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष के कुलदीप सिंह पठानिया के पिछले दिन दिये गये ब्यान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा छः विधायकों का सर कलम कर देने और तीन विधायकों के सर आरी के नीचे हैं होने जैसे बात करना दुर्भाग्यपूर्ण हैं। एक संवैधानिक एवं गरिमापूर्ण पद पर बैठे किसी भी माननीय द्वारा इस तरह की बात करना समझ से परे है। हिमाचल की यह संस्कृति नहीं रही है। इस तरह के ब्यानों की हिमाचल जैसी देवभूमि में कोई जगह नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में वह कांग्रेस सरकार को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल के इतिहास में उनके द्वारा गरिमा एक विपरीत किया गया आचरण याद किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सब कार्य सरकार को ग़लत तरीक़े से बचाने के प्रयास हैं। सरकार को बार-बार बचाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा की जा रही है। बजट पास करवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों को निष्कासित करके सरकार बचाई। यह सरकार संख्याबल और लोगों की नज़रों में गिर चुकी है, नैतिकता के आधार पर इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

क्या कांग्रेस से निकलते .....पृष्ठ 1 का शेष

विधानसभा से निष्कासित होकर भाजपा में शामिल हो गये। करीब पन्द्रह माह तक कांग्रेस के वफादार सिपाही बनकर मुख्यमंत्री का समर्थन करते रहे हैं। भुट्टो ठेकेदार हैं और एक स्टोन क्रेशर भी चला रहे हैं। लोक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी विभागों में अरसे से ठेकेदारी करते आ रहे हैं। यह ठेकेदारी विधायक बनने से बहुत पहले से चल रही है। लेकिन विभाग की शिकायतों पर पहली बार उनके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज हुये हैं। यह मामले दर्ज होने पर उभरी प्रतिक्रियाओं में यह कहा जा रहा है कि क्या चुनाव के दौरान ही यह धोखाधड़ी विभाग के संज्ञान में आयी है। जब पन्द्रह महीने तक भट्टो कांग्रेस के विधायक थे तब वह पाक साफ थे और भाजपा में शामिल होते ही अपराधी हो गये हैं। इस चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने कांग्रेस के छः बागियों के भाजपा में शामिल होने को बिकाऊ होने की संज्ञा देते हुये पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर केंद्रित करने का प्रयास किया है। इसी प्रयास में इन बागियों को भू-माफिया और खनन माफिया तक करार दिया है। धर्मशाला में सुधीर शर्मा को भू-माफिया करार देते हुये मुख्यमंत्री ने यहां तक आरोप लगाया है कि सुधीर शर्मा ने 82 संपत्तियों में अपने ड्राइवर के नाम पर निवेश किया है। मुख्यमंत्री के इन आरोपों का जवाब देते हुये पलटवार करके जो आरोप सुक्खू पर दस्तावेजी प्रमाणों के साथ लगाये हैं वह बहुत गंभीर है। बागियों को बिकाऊ करार देने को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले दायर हैं। आने वाले दिनों में यह मामले किस हद तक कैसे आगे बढ़ते हैं इस पर सब की नज़रें लगी रहेंगी। सुधीर शर्मा ने जो आरोप मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाये हैं उनके दस्तावेजी प्रमाण और पूरा खुलासा जनता में किस तरह सामने आता है यह देखना रोचक होगा। लेकिन यह तय है कि इस चुनाव प्रचार में दोनों पक्ष जिस हद तक जनता के सामने आ गये हैं उससे पीछे हटना किसी के लिये भी संभव नहीं होगा।